अब कोरोना का दोष जनता पर ही मढ़ने की तैयारी

शकील अख़्तर

इस बार चोट मध्यम वर्ग को पड़ेगी। टीवी पर डिबेटें देख-देखकर वह सबसे ज़्यादा खुश हो रहा था। कोरोना जब पिछले साल शुरू हुआ तो न्यूज़ चैनलों के लिए यह एक इवेंट था। सबसे पहले उन्होंने इसे 'लाल' बनाने में अपनी पूरी अक्ल लगा दी। महामारी है, विश्वव्यापी असर हो रहा है, सब भूलकर इसे चीन का 'लाल आतंक' निरूपित करने में लग गए। एक रेफ्रिजरेटर की कहानी, एक चमगादड़ की जबानी, बैक्टीरिया से दुनिया पर कब्जा जमा लेने की साजिश से लेकर नेहरू की 1962 की भूल, सब पर दिन भर प्रोग्राम बनने लगे। एक चैनल तो कोरोना का जिन्दा वायरस ही पकड़ कर स्टूडियो में ले आया।

सेनेटाइज़र कहां है, किसी को नहीं मालूम। स्टोरों से गायब हो गया। यहां तक कि सुरक्षा बलों की कैंटीनों तक में सप्लाई नहीं हो रही थी। मनमानी कीमतों में ब्लैक में मिल रहा था। क्वालिटी की कोई गांरटी नहीं थी। दूसरी तरफ, केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (अब स्वर्गवासी) रामविलास पासवान अपने दफ़्तर में सेनेटाइज़र के बड़े-बड़े जार लगाकर बता रहे थे कि देखिए कैसे सेनेटाइज़र का उपयोग किया जाता है। इसे हाथ से भी चला सकते हैं, और पांव से भी! उस समय संसद चल रही थी। जब वहां सवाल हुए तो सेनेटाइज़र को आवश्यक वस्तु में अधिसूचित किया गया। उसके दाम निर्धारित किए गए। मगर उसकी कालाबाज़ारी रोकने की कहीं बड़ी कोशिश नहीं की गई। आज जब जनता पर सब कुछ डालने का प्रचार तेज कर दिया गया है तो क्या यह पूछा जा सकता है कि पिछले साल मार्च में जिस सेनेटाइज़र पर सबसे ज्यादा जोर था, उसे नकली बनाने, ज़्यादा कीमत वसूल करने वाले कितने उत्पादकों, बड़े होलसेलरों को जेल हुई। या उसका ठीकरा भी जनता पर फोड़ा जा सकता है।

उस समय साबुन की भी कमी हो गई थी। ख़ासतौर से उन साबुनों की जो कीटाणुनाशक टैग के साथ बिकते हैं। एक तरफ हाथ साबुन से धोते रहो का उपदेश

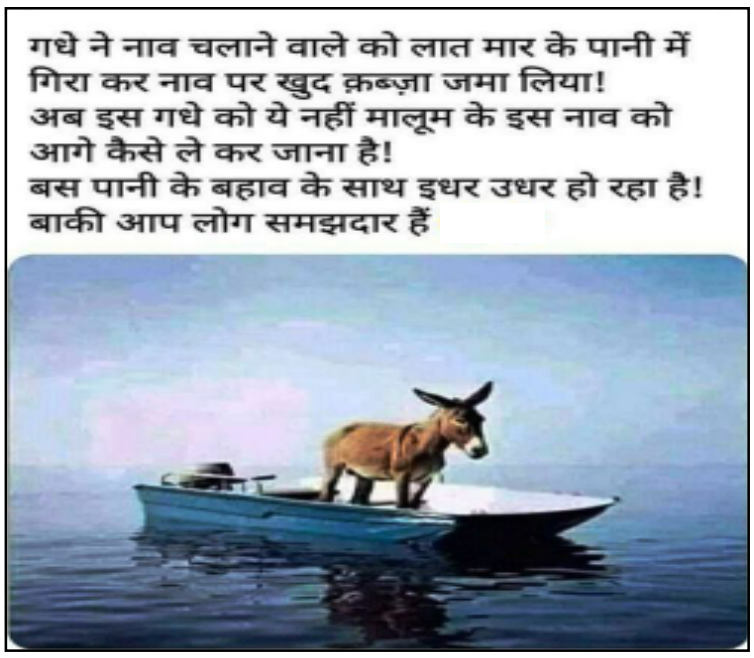

तो दूसरी तरफ गांवों में जागरूकता फैलाने के लिए पांच रुपए वाला साबुन भी मुफ़्त में न बांटने की समझ! और तीसरी तरफ करोड़ों का काढ़ा सरकारी खर्च पर मुफ्त बांटने का दावा। इसी तरह उस मास्क की सबसे ज्यादा लापरवाह व्याख्या की गई, जिसे आज 'लहर दो' में सबसे ज़रूरी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि मास्क या गमछा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहां इस तरह के आसान विकल्प देना किस तरह घातक हो सकता है- यह आज मास्क पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देने से समझ में आ रहा है। कुछ मंत्री कह रहे थे कि वे मास्क नहीं पहनते। बहुत सारे उदाहरण हैं और सबको मालूम है कि मास्क को कैसे अवांछित बनाया गया। मगर आज यह इल्जाम भी ग़रीब पर डाला जा रहा है। उसे पकड़कर बेरहमी से मारा जा रहा है। 'जनता ही नालायक है' का रिकार्ड फिर से बजाया जाने लगा है।

ख़ैर, तो हम बात कर रहे थे कि मीडिया ने किस तरह गैरजिम्मेदारी और सरकार पर आंच न आने देने के उद्देश्य से आरोप मढ़े। और कैसे इस धुन पर मध्यम वर्ग झूमता रहा। तो जब कोरोना को लाल करने का माहौल कमजोर पड़ने लगा तो मीडिया के भाग्य से फिर छींका टूटा। दिल्ली में तब्लीग़ी जमात के सम्मेलन का मामला सामने आ गया। यह तो इनका सबसे पसंदीदा विषय था। वे फ़ौरन कोरोना को 'हरा' करने में जुट गए। जाने कितने पत्रकार थूक एक्सपर्ट बन गए। 'मैंने थूकते हुए देखा', 'मैंने भी देखा' से लेकर 'पाकिस्तान ने भेजे कोरोना बम', 'बिरयानी की मांग', 'पजामा उतारा', 'छुपे हुए हैं' तक जाने कितनी कहानी मीडिया ने बना डालीं। उस समय लिखे एक लेख में हमने आगाह किया था कि सांप्रदायिक रंग देने से कोरोना ख़त्म नहीं होगा। मगर इसी हिन्दू-मुसलमान में तो टीवी की जान बसती है। इसे वह कैसे छोड़ सकती थी।

जब हर अदालत ने यह साफ़ कर दिया कि जमात का कोई दोष नहीं था, महज एक संयोग था। तब तक वे कोरोना वायरस का पोस्टमार्टम करते रहे और उसमें से सांप्रदायिक एंगल निकलते रहे। लेकिन जब जमात के मुखिया मौलाना साद को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया, तब जाकर मीडिया को लगा कि अब इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन वह कोरोना से निपटने के वास्तविक रास्तों पर फिर भी नहीं लौटी। इस बार उसने सबसे सॉफ़्ट टारगेट बनाया मज़दूरों को। पैदल जाता हुआ बेबस मज़दूर इनका शिकार बना। क्या-क्या झूठ नहीं बोला गया सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते बच्चों, औरतों और वृद्धों के बारे में। यह रिपोर्टिंग उतनी ही अमानवीय थी, जैसे राक्षस, राम-सीता वनगमन की कहानी लिखें! अगर तुलसी का लिखा यह सच है कि- 'तुलसी आह गरीब की कबहूं न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौह भस्म होई जाए!' तो पता नहीं इन गरीब मज़दूरों की मजबूरी का मज़ाक उड़ाने वालों का क्या होगा? मज़दूरों के बाद ये किसानों के पीछे पड़ गए और अब तो पूरी जनता के।

मगर यह पूछने वाला कोई नहीं है कि वैक्सीन क्यों नहीं है? तमाम राज्यों में रेमडेसिवीर इंजेक्शन भी ब्लैक में क्यों मिल रहे हैं? वेन्टिलेटर क्यों नहीं हैं? और सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन को लेकर रहस्य क्यों बनाया जा रहा है? पारदर्शिता बरतने में नुक़सान क्या है? टीवी का अपना खेल है, वह क्यों पूछेगी? लेकिन अब पानी सिर के ऊपर आ गया है। जनता के नहीं, मध्यम वर्ग के। ग़रीब जनता तो पिस चुकी, जितना पिसना था। एक साल में उसका तेल निकल गया। अब उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब गाज गिरेगी मध्यम वर्ग पर। वह सबकी पिटाई पर बहुत खुश हो रहा था। उसे लगता था सरकार वही है। उसका नंबर कभी नहीं आएगा। लेकिन अब वॉट्सऐप ग्रुपों पर माहौल बनना शुरू हो गया है।

ये ग्रुप ही अब भारत में ज्ञान के नए केन्द्र हैं। टीवी भी इन्हीं से प्राप्त ज्ञान पर चलता है। देश का मध्यम वर्ग जो कभी नेतृत्व देता था। आज वाट्सऐप ग्रुपों और टीवी से संचालित होता है। उसकी नौकरी जा रही है, नौकरी है तो वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन है तो कम मिल रहा है। मगर इन सबके बावजूद वह कोई सवाल नहीं पूछता है। सुबह वाट्सऐप ग्रुप देखकर फॉरवर्ड-फॉरवर्ड खेलता है और रात को एक से एक जहरीली टीवी डिबेट देखकर काल्पनिक शत्रु से लड़ने के प्लान बनाते हुए सो जाता है। वह इस कदर नशे में आ गया है कि जब चीन की घुसपैठ के लिए सरकार को नहीं, फ़ौज को दोषी बताया गया तब भी सोशल मीडिया की भाषा में सहमत, सहमत चिल्लाता रहा। टीवी ने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी कि कैसे उसने फ़ौज का मनोबल गिराया है। ख़ैर, माफ़ी तो उसने इसकी भी नहीं मांगी थी, जब उसने चैनल पर बलात्कार का नाट्य रूपान्तरण दिखाना शुरू किया था। उससे ज्यादा अश्लील, वीभत्स और महिला-विरोधी कुछ नहीं था। और सबसे बढ़कर गैरकानूनी, आपराधिक कृत्य था। मगर वह उसी तरह गैरजवाबदेह बना रहा, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आत्महत्या को हत्या बनाने की असफल कोशिशों के बाद रहा!

इस सबके बावजूद टीवी चैनल बड़ा मुद्दा नहीं हैं। कभी भी, कोई भी एक झटके में इन्हें सही कह सकता है। झूठी तारीफ़ें हमेशा पसंद नहीं की जाती हैं। जब कभी उलटी बयार बहती है, तो सबसे पहले उन्हीं को पकड़ा जाता है जो अनुकूल हवाओं के झूठे गान सुनाते रहते हैं। नेता जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है, जानता है कि यह मेरी नहीं, सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं। चिन्ता है देश के उस मध्यम वर्ग की जो कभी पढ़-लिख कर विदेशों में गया था। भारत की आज जो दुनिया में पहचान है, वह पढ़े-लिखे होने की वजह से है। कल ये वाट्सऐप के पढ़े और टीवी के सीखे लोग क्या दुनिया में भारत की वही छवि कायम रख पाएंगे, जो आज़ादी के बाद बनी थी। कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा। टीवी भी कुछ और हो जाएगा। मगर पीढ़ियां बनने में समय लगता है। पता नहीं कितने लोगों ने मंटो की मशहूर कहानी 'शाहदौले के चूहे' पढ़ी है। वही कहानी याद आ रही है। हमारा मध्यम वर्ग उसी तरफ जाता दिख रहा है।

जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को क्या हुआ था

राजीव अहीर

अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। शुरू में प्रदर्शनकारियों ने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। भारतीयों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और खाली सड़कों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की। 9 अप्रैल को, राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डा. सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और वे 10 अप्रैल, 1919 को सन्यासियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डा. सत्यपाल व डा. किचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप से लिया। पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया। बड़ी तादाद प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे काफी तनाव फैल गया। दंगे में पांच अंग्रेज भी मारे गए और मार्सेला शेरवुड, एक अंग्रेज मिशनरी महिला जो साइकिल पर जा रही थी, को पीटा गया।

उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत सैनिक टुकड़ी को भेजा गया। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंपी गई डायर ने, हालांकि 15 अप्रैल, 1919 को एक घोषणा जारी की कि लोग पास के बिना शहर से बाहर न जाएं और एक समूह में तीन लोगों से अधिक लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभाएं न करें।

बैसाखी के दिन आस-पास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए नगर के लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया। त्योहार के

आयोजन के बीच विरोध-प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जिसमें दो प्रस्ताव-रौलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा प्रस्ताव-पारित किए गए। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया।

डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गयीं, जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गयीं। सभा स्थल के सभी निकास मार्गों के सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियों से छलनी होते रहे। इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गये, जिसमें युवा, महिलायें, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहशी क्रूरता ने देश का मान तार तार कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की निन्दा की गयी। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विरोधस्वरूप अपनी 'नाइटहुड' की उपाधि त्याग दी तथा शंकरराम नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधीजी ने सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया। उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। ए.पी.जे. टेलर, इतिहासकार, लिखते हैं- जालियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था, जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। 1919 की घटना ने पंजाब की प्रतिरोध या विरोध-प्रदर्शन की राजनीति को आकार प्रदान किया। भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस जनसंहार को ऐसे कृत्य के रूप में देखा जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न संताप से उबरने में मदद करेगा।

उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसने पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन को वीभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया, लंदन जाकर हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1940 में फांसी की सजा दी गई। वर्ष 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया।

(राजीव अहीर की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास के अंश, प्रकाशक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन)

योगी बनाम मोदी: झूठ पकड़ा गया

हाल ही में द हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप का टाइम्स नाउ, न्यूज नेशन चैनल. टीवी 9 भारतवर्ष, आजतक जैसे अखबार और चैनलों समेत असंख्य आरएसएस संचालित मीडिया ने एक रिपोर्ट दिखाई और प्रकाशित की। जिसमें कहा गया कि हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी रिपोर्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए लिखा गया कि पिछले साल प्रवासी मजदूरों के संकट को बहुत अच्छी तरह संभाला। लेकिन आल्ट न्यूज ने 16 अप्रैल को एक फैक्ट चेक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई स्टडी ही नहीं की तो योगी की तारीफ कैसे करेगी। इस तरह योगी को लेकर आरएसएस का यह फर्जी प्रचार बेनकाब हो गया। वह मोदी के मुकाबले योगी को खड़ा करना चाहता है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रहा है।

हरियाणवी बयानवीर

कोरोना की आड़ में किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है तानाशाह सरकार! सरकार की नाकामियों की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। एक तरफ स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थान बंद किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी रैलियां धड़ल्ले से की जा रही हैं। सरकार ने किसानों के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए है। सरकार को चाहिए कि वो अपने गुरुर को छोड़कर जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करें, ताकि सभी किसान सुरक्षित अपनें घरों को लौट सकें।

-अभय सिंह चौटाला, राष्ट्रीय महासचिव, इनैलो

सरकार मानवता के लिए किसानों से आंदोलन समाप्त करने को कह रही है। सरकार ऐसे संकटकाल में भी अपना घर परिवार छोड़ आंदोलन कर रहे किसानों का दर्द कब समझेगी? सरकार से भी आग्रह हैं मानवता के लिए आप अपनी जिद छोड़िए, किसानों की माँग मानते हुए, उन्हें घर लौटा दीजिए।

-दीपेन्द्र हुड्डा, राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस